न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी :: नमित मेहता, आई.ए.एस

विविध :: 09 / 2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024 / 75

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
State Bank of India, Stressed Assets Management Branch-I, 12th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan 1, Tolstoy Marg, New Delhi. जरिये प्राधिकत अधिकारी–सुधीर कुमार		1. M/s M.D. Suitings Private Limited G-120, RIICO Phase-1&2, Industrial Area Biliya, Bhilwara. 2- Pradeep kumar Surolia s/o Yugal kishore Surolia, I-2, Basant Vihar, Bhilwara 3- Prashant Surolia s/o Yugal kishore Surolia, I-2, Basant Vihar, Bhilwara 4- M/s SPNR Esolutions Private Limited, Through its Directors Pradeep kumar Surolia s/o Yugal kishore Surolia & Prashant Surolia s/o Yugal kishore Surolia. 307, Apeejey House, 130 Bombay Samachar Marg Fort, Mumbai.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्ट्रेस्ट, 2002</u>

दिनांकः– 03.04.2024

1. प्राधिकृत अधिकारी, **भारतीय स्टेट बैंक** द्वारा वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 SARFAESI Act 2002 की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना–पत्र जरिये **प्रतिनिधि श्री राम निवास स्वामी ने मैसर्स एम0डी0 सूटिंग्स वगैरह** के विरूद्ध प्रस्तुत कर, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत् ऋण के समय रखी गयी गिरवी सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

2. कम्पनी के उपस्थित अधिवक्ता / प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह बताया कि अप्रार्थी / ऋणी को बैक / कंपनी द्वारा कुल **15,39,00,000 / – रूपये** (11,50,00,000 / –रू0, 2,29,00,000 / –रू0, 1,15,00,000 / – रू0 एवं 45,00,000 / –रू0) **(रूपये पन्द्रह करोड उनचालीस लाख) का मोरगेज लोन का ऋण** स्वीकृत किया गया। इस ऋण की एवज में निम्न जायदाद / सम्पत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

1. Factory Land & Building situated at G-120, 1 and 2 Phase, RIICO Industrial Area, Biliya, Bhilwara, Rajasthan Admeasuring area 2025.84 Sq. Meter in the name of M/s M.D. Suitings private Limited through its Directors Pradeep kumar Surolia s/o Yugal kishore Surolia & Prashant Surolia s/o Yugal kishore Surolia <u>Bounded by</u>- North : Plot no. 119, South : Plot no. G-122&G-121(b), East: III^rd Phase Plot no. F-249 & 250, West: RIICO Road 18 Meter Wide.
2. Factory Land & Building situated at G-119, RIICO Industrial Area 1 and 2 Phase, Biliya, Bhilwara, Rajasthan Admeasuring area 1917.15 Sq. Mtrs. in the name of M/s M.D. Suitings through its Partners Pradeep kumar Surolia s/o Yugal kishore Surolia & Prashant Surolia s/o Yugal kishore Surolia Bounded by- North : Plot no. G-118, South : Plot no. G-120, East: Plot no. F-250 & 251, West: Road

3. चूंकि ऋणी फलस्वरूप अप्रार्थी **मैसर्स एम0डी0 सूटिंग्स प्रा0लि0 वगैरह** के द्वारा बैंक / कम्पनी से प्राप्त किये गये ऋण के पेटे प्रार्थी के पक्ष में ऋणी एवं जमानतियों द्वारा गारंटी, करार एवं दस्तावेजो पर अपने हस्ताक्षर कर इसे निष्पादित कर दिये गये थे, परन्तु उक्त ऋणी द्वारा बैंक से प्राप्त की गयी ऋण राशि का भुगतान नहीं किये जाने से ऋणी के ऋण खाते को दिनांक **29.11.2022** को एन.पी.ए. (Non Performing Asset) घोषित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

4. फलस्वरूप अप्रार्थी **मैसर्स एम0डी0 सूटिंग्स प्रा0लि0 वगैरह** के द्वारा SARFAESI Act के तहत ऋण राशि मय ब्याज **15,34,68,662.14/– (पन्द्रह करोड चौतीस लाख अडसठ हजार छः सौ बासठ रूपये चौदह पैसे)** दिनांक **28.02.2023** तक ब्याज शामिल करते हुए भुगतान हेतु बकाया है। SARFAESI Act की धारा 13(2) के तहत बकाया भुगतान करने हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक **08.03.2023** को भेजा गया इसके बाद भी अप्रार्थी ने देय राशि का भुगतान कंपनी को नहीं किया।

5. फलस्वरूप अप्रार्थी **मैसर्स एम0डी0 सूटिंग्स प्रा0लि0 वगैरह** द्वारा देय ऋण राशि का 60 दिवस व्यतीत होने के उपरान्त भी भुगतान नहीं किये जाने से प्रार्थी कम्पनी द्वारा व्यथित होकर सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत इस न्यायालय में ऋणी द्वारा ऋण पेटे गिरवी रखी गयी सम्पत्ति जो कि प्रार्थना पत्र में वर्णित है, का कब्जा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया।

6. प्रार्थी **कम्पनी/बैंक** के इस प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थी पक्ष को तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस दिया गया। अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

7. हमने प्रार्थी के द्वारा सरफेसी की धारा 14 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी ने ऋण का भुगतान कर दिया गया हो। सरफेसी एक्ट के तहत इस न्यायालय को मात्र पुलिस ईमदाद देने की हद तक सीमित अधिकार है। प्रार्थना पत्र एवं इसके लगाये दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/कंपनी के द्वारा फलस्वरूप **मैसर्स एम0डी0 सूटिंग्स प्रा0लि0 वगैरह** को ऋण वसूली हेतु इस अधिनियम की धारा 13(2) में नोटिस दिया गया है, जिसका संवहन (Deliver) ऋणी को हो जाना स्पष्टतया पाया जाता है। तदुपरान्त भी निर्धारित 60 दिवसीय अवधि समाप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के नही चुकायी गयी है, जबकि दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेसियर्स एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट अधिनियम –2002 की धारा 14 में रहन (Mortgage) रखी गयी सम्पत्ति को कब्जे में ली जाकर प्रार्थी को दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है जो इस प्रकार है :–

Section 14 Chief Metropoitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured assest - (1) where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provision of this act, the secured creditor may , for the purpose of taking possession or control of any such secured assest, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the Distric Magistrate withing whoes jurisdisction any such secured assest or other documents relating theirto may be situlated or found, to take possession thereof , and the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, the Distric Magistrate shall, on such request being made to him -

(a) take possession of such assest and documents relating thereto ; and
(b) forward such assest and documents to the secured creditor

Provided that any application by the secured creditor shall be accompanied by an affidavit duly affirmed by the authorised officer of the secured Creditor, declaring that:

(i) the aggregate amount of financial assistance granted and the total claim of the bank as on the date of filing the application.

(ii) The borrower has created security interest over various properties and that the Bank or Finicial Institution is holding a valid and subsisting security interest over such properties and the claim of the Bank or the Financial is within the limitation period.

(iii) The borrower has created secutity interest over various properties giving the details of properties refferred to in the sub clause (ii) above :

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

की अवधि में ऋण का भुगतान नहीं करता है तो पैरा संख्या 2 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पति को नियमानुसार कब्जे में लिए जाने के लिए **उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** को निर्देश प्रदत्त किये जाते है तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने से पूर्व प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करके एवं यदि संपत्ति में कोई किरायेदार है तो उस संपत्ति को छोड़ने हेतु समुचित समय देने के उपरांत ही पैरा 2 में वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण (कब्जा) कर प्रार्थी कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द करेंगे। **यदि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा बकाया ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो इस आदेश की कार्यवाही नहीं की जावें।** जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा सम्बन्धित अधीनस्थ पुलिस उप अधीक्षक को इस आदेश की पालना हेतु **उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** को आवश्यकतानुसार प्रार्थी के खर्चे पर समुचित पुलिस बल उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करेंगे। **उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पति किसी भी न्यायालय के स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी बैंक/कंपनी, अप्रार्थीगण को देवें।**

9. आदेश आज दिनांक 03-04-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नमित मेहता)
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)